>

Title: Need to set up medical centres for free treatment of cancer patients.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, गुलाम नबी आजाद, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में कैंसर पेशंट्स की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर के इलाज में काफी खर्च होता है, क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा है। आम आदमी कैंसर का इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। अगर किसी घर में कोई कैंसर पेशंट होता है तो पूरा परिवार कर्ज से डूब जाता है और सालों-साल तक कर्ज चुकाने के लायक नहीं रहता।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप कोई ऐसा सेंटर बनाएं जहां कैंसर पेशेंट्स का फ्री में इलाज हो सके और वह सरकार की तरफ से हो, क्योंकि गरीब लाखों रुपए खर्च करके कैंसर का इलाज नहीं करा सकते और वे अपने मरीज को मरता हुआ देखते रहते हैं।

मेरा इस सम्बन्ध में दूसरा सुझाव यह है कि एमपी लैड से एक राशि 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी जाए, जिससे सांसद किसी कैंसर पीड़ित का एम्स में, टाटा मेमोरियल अस्पताल में या राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में सीधे इलाज करा सकें और वह राशि सीधे एमपी लैड फंड से इन अस्पतालों में चली जाए।

वह सीधा जाए जिससे उन लोगों की दुर्दशा न हो। जिस तरह से वे रोते हैं, जिस तरह से उन परिवारों का बुरा हाल होता है, वह हमसे देखा नहीं जाता है। माननीय गुलाम नबी आजाद जी बैठे हैं, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Jitendra Singh Bundela, Shri Dhnanjay Singh, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri Arjun Meghwal, Shrimati Botcha Jhansi Laskhmi, Shri Dara Singh Chauhan are allowed to associate with the matter raised by Shri Jai Prakash Agarwal..

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर, इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। साथ ही सदन के द्वारा अपने देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में केंसर और डायबिटीज के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा केंसर और डायबिटीज के मरीज हमारे देश में होंगे। इसके लिए सरकार ने इसी साल एक योजना बनाई है और 100 जिले हमने 21 राज्यों में चुन लिये हैं। इसके लिए एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया गया है और 4-4, 5-5 जिले 21 राज्यों में लिए गये हैं। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को केन्द्रीय सरकार से, अर्ली डिटेक्शन के लिए, डेढ़ करोड़ रुपया मशीनरी के लिए, पहले दे दिया गया है। तकनीशियन्स के लिए भी पैसा दे दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट में 100 मरीजों के लिए 1 लाख रुपये के हिसाब से कीमोथ्रैपी के लिए भी हमने पैसा दिया है। इस तरह से 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 हजार मरीजों के लिए, एक लाख रुपये के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं और अगले एक-दो सालों में यह कार्यक्रम हम पूरे देश में शुरू करने वाले हैं।

बीपीएल की जो स्कीम पूरे देश के लिए है वह अब सर्टिफिकेट से नहीं चलेगी, बल्कि काड्र्स होल्डर्स पर लागू होगी। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट्स कैसे बनते हैं, इसलिए बीपीएल कार्ड होल्डर्स के केंसर के इलाज का पूरा पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय देगा, चाहे पांच लाख रुपये लगें या सात लाख रुपये लगें, हम पूरा पैसा देंगे। ...(व्यवधान) इससे अलग का कोई प्रयोजन नहीं है।